



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 2018 / 00186

दर्ज तिथि:- 19.02.2018

1. गुलाब पत्नी श्योकरण
2. हरफूल पुत्र श्योकरण
3. मदनलाल पुत्र श्योकरण
4. मेवा पुत्री श्योकरण

समस्त बालिग जातियान बलाई निवासीयान किशोरी तहसील थानागाजी अलवर

5. लक्ष्मा पत्नी श्रीकिशन जाति मीना निवासी किशोरी तहसील थागागाजी अलवर राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम्

1. मामराज पुत्र भौरैलाल
2. नन्दलाल पुत्र भौरैलाल
3. गुलाब बेवा भौरैलाल
4. गोपाल पुत्र भौरैलाल

समस्त जातियान दर्जी निवासीयान किशोरी तहसील थागागाजी अलवर राज0

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता-श्री लक्ष्मण पोसवाल।

अप्रार्थी अधिवक्ता:- श्री चन्द्रशेखर शर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

दिनांक 03.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 2104 / 1.25 है0, 2104 / 2417 / 0.02 है0, 2109 / 0.75 है0, वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कृषि काश्त के लिए ग्राम किशोरी-गोपालपुरा पक्की सड़क के तरफ दक्षिण की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2041 / 2406 / 0.64 है0, 2106 / 0.38 है0, 2105 / 0.28 है0 वाके ग्राम किशोरी में से पश्चिम की तरफ से उक्त खसरों की डोल के सहारे-सहारे से होकर



उत्तर से दक्षिण की ओर 15 फुट चौड़ा कच्चा मार्ग जारी है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण की आराजी तक कृषि कार्य हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण रिकॉर्डेड रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त मौके पर चालू रास्ते, जिसे नजरी नक्शा में रंग लाल से दिखाया गया है, को विस्तारित करते हुये करीब 15 फीट चौड़ाई में किशोरी-गोपालपुरा सडक से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक लंबाई में राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित कराये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा हाल आराजी खसरा संख्या 2041/2406, 2106 एवं 2105 में उत्तर-दक्षिण लम्बाई में 15 फुट चौड़ाई के रास्ता मांगा है। अप्रार्थी के पास बहुत कम मात्रा में खातेदारी भूमि चली आती है जिससे कई हिस्सेदारान के पास केवल 01 जरीब से भी कम आराजी रह जायेगी। जिससे शेष आराजी अप्रार्थी के कृषि-कार्य के लिए अनुपयोगी साबित होगी। प्रार्थी गोपालपुरा सडक के आराजी खसरा संख्या 2116, 2112, 2111, 2110 तथा 2110/2404 जो कि सिवायचक भूमि राज्य सरकार की चली आती है, में से खसरा संख्या 2109 में पहुँचकर अपनी काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी की आराजी में से नहीं गये है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को केवल परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में गोपालपुरा सडक से आराजी खसरा 2041/2405 सिवायचक भूमि से होते हुए रास्ता प्रस्तावित किया है जो राज्य सरकार की भूमि है ऐसे में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी को पक्षकार नहीं बनाया। अंत में प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जाँच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2023/1240 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।
4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए किशोरी-गोपालपुरा पक्की सडक के तरफ दक्षिण की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2041/2406/0.64 है0, 2106/0.38 है0, 2105/0.28 है0 वाके ग्राम किशोरी में से पश्चिम की तरफ से उक्त खसरों की डोल के सहारे-सहारे से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर 15 फुट चौड़ा कच्चा मार्ग जारी है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण की आराजी तक कृषि कार्य हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण रिकॉर्डेड रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त मौके पर चालू रास्ते, जिसे नजरी नक्शा में रंग लाल से दिखाया गया है, को विस्तारित करते हुये करीब 15 फीट चौड़ाई में किशोरी-गोपालपुरा सडक से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक लंबाई में राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित कराये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंचने हेतु एक अन्य मौके पर चालू आम रास्ते का विकल्प बताते हुये प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं बताते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

**धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहाँ**

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जाँच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहाँ-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

**68. Application under Sec. 251-A.** - *An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

**69. Enquiry and disposal of application.** - *On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

*(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*

*(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.*

**70. Determination of compensation.** - *(1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

*(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.*

*(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-*

*(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and*

*(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the*

*Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.*

*(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार हैं-
1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकार्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
  2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
  3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।
7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। इस बाबत तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 25.04.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। उक्त तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग के विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प रिकॉर्ड व मौका अनुसार उपलब्ध होना प्रतीत नहीं होता है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. साथ ही प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण अनुपस्थित तथा प्रार्थीगण मौके पर उपस्थित मिले। प्रार्थीगण द्वारा आवेदित मौके पर चालू रास्ते के साथ-साथ अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में सुझाये गये वैकल्पिक रास्ते के विकल्प के साथ प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता तथा

तत्पश्चात् लघुत्तम मार्ग के परीक्षणों के तहत प्रार्थना-पत्र के तथ्यों के संदर्भ में मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि प्रार्थी द्वारा आवेदित कदीमी रास्ता करीब 8-10 फीट चौड़ाई में मौके पर चालू है। इसके साथ ही प्रार्थीगणों की आराजी तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर चालू नहीं मिला। इसके पश्चात् प्रार्थीगणों की आराजी तक पहुंच हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प के तौर पर प्रार्थीगणों द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम रास्ता हेतु मार्ग उचित प्रतीत हुआ। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 25.04.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 25.04.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/2023/1240 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काबिल-ऐ स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार थानागाजी की दिनांक 25.04.2023 की मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग 15 फुट चौड़ाई का गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

**आदेश है कि**

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/2023/1240 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण के पश्चात् प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के निष्कर्ष के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 25.04.2023 की मौका जाँच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित 15 फुट चौड़ाई के हाल आराजी खसरा संख्या 2539/2041 के मौके पर चालू रास्ते के आगे से हाल आराजी खसरा संख्या 2041/2406, 2106, 2105 में से रास्ते में आयी भूमि की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम-70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर

नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या-1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावे। दिनांक 25.04.2023 की मौका जाँच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावे।

अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि के बाबत उभय पक्षकारों के मध्य सहमति हो तो मुताबिक सहमति मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को करना सुनिश्चित करे। अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारों के मध्य सहमति नहीं हो तो, तहसीलदार थानागाजी निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्तर्गत उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि आंकलित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित करते हुये प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि जमा कराने हेतु तथा अप्रार्थीगणों को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुये सूचित करे। प्रार्थीगण उक्त नोटिस की अवधि से पूर्व तहसीलदार थानागाजी द्वारा आंकलित राशि नियमानुसार जमा करावे तथा अप्रार्थीगण उक्त नोटिस की अवधि से पूर्व अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करे। साथ ही प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि उपलब्ध करवाने का विकल्प तहसीलदार थानागाजी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अप्रार्थीगण अगर सहमत हो तो अप्रार्थीगणों को भूमि के बदले भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जावे। उक्त नोटिस की अवधि समाप्ति के पश्चात तहसीलदार थानागाजी प्रार्थीगण के नियमानुसार मुआवजा राशि नियत तिथि तक जमा कराने तथा अप्रार्थीगण द्वारा नियत तिथि तक मुआवजा राशि/भूमि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मुआवजा राशि को निर्धारित मद में जमा करते हुये उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर उक्त रास्ते को चालू कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी-अलवर